

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 13167/2024

मेसर्स श्री शर्मा स्टीलटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय खसरा संख्या 245/264, ग्राम बावरी, बेनाड रोड, सरना में है। डूंगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री के माध्यम से सरवन कुमार शर्मा।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, भवानी सिंह रोड, अंबेडकर सर्किल, सी स्कीम, जयपुर, राजस्थान आयुक्त के माध्यम से।
- उपायुक्त (राज्य कर), वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बी, प्रवर्तन शाखा-II, कर भवन, जयपुर।
- भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:

श्री वागीश कुमार सिंह,  
सुश्री साक्षी अग्रवाल द्वारा सहायता प्राप्त

प्रतिवादी(ओं) के लिए

श्री संदीप तनेजा, एएजी  
सुश्री किंजल के साथ सुराना - प्रतिवादी संख्या  
1 और 2  
श्री पवन के लिए पारीक - प्रतिवादी नंबर 3 के  
लिए - यूओआई

माननीय श्रीमान. जस्टिस पंकज भंडारी

माननीय श्रीमान. जस्टिस प्रवीर भटनागर

आदेश

प्रकाशनीय:

**13/08/2024**

- याचिकाकर्ता ने जीएसटी डीआरसी-01 ए के तहत दिए गए नोटिस के अनुसरण में दिए गए उत्तर पर विचार न किए जाने से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि राजस्थान माल और सेवा कर (आरजीएसटी) / केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) नियम, 2017 (संक्षेप में "2017 के नियम") के नियम 142 (1 ए) के अनुसार, नोटिस दिया जाना है और यदि नियम 2017 के नियम 142 (2 ए) के तहत जवाब दिया जाता है, तो अधिकारियों को नियम 142 (1) (ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले जवाब पर विचार करना आवश्यक है।
3. यह भी तर्क दिया गया है कि नियमों या अधिनियम के तहत सुनवाई का अवसर देने का कोई प्रावधान नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रावधानों की व्याख्या की है और माना है कि कारण बताओ सूचना से पहले भी, अधिकारियों को 2017 के नियम 142(1) (ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। इस संबंध में, ईडन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम वरिष्ठ संयुक्त राजस्व आयुक्त कोलकाता दक्षिण सर्कल, डब्ल्यूबीजीएसटी और अन्य : डब्ल्यूपीए संख्या **1025/2024** के मामले में 07 फरवरी, 2024 को पारित निर्णय के साथ-साथ डायमंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया गया है। सीजीएसटी और सीएक्स के सहायक आयुक्त, तलतला डिबीजन II कोलकाता दक्षिण आयुक्त और अन्य : 2023 के आईए नंबर कैन 1 में एमएटी **1948/2023** ने **15 फरवरी, 2023** को निर्णय लिया।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले से भिन्न नहीं है और वर्तमान मामले में भी सूचना का उत्तर दिया गया था, परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने का निर्देश दिया जाए और फिर, यदि आवश्यक हो, तो नियम 2017 के नियम 142(1) (क) के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए।
5. विद्वान अपर महाधिवक्ता अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए हैं।
6. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 2017 के नियमों के नियम 142(1 ए) के अंतर्गत प्रावधान केवल सूचना देने का है, वह भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रयुक्त शब्द "उचित अधिकारी कर सकता है" है। यह भी तर्क दिया गया है कि 2017 के नियमों के नियम 142(2 ए) में प्रावधान है कि यदि उप-नियम (1 ए) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे दी गई राशि का

आंशिक भुगतान कर दिया है या प्रस्तावित देयता के विरुद्ध कोई प्रस्तुतिकरण दाखिल करना चाहता है, तो वह फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 ए के भाग बी में ऐसी प्रस्तुतिकरण कर सकता है।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि 2017 के नियम 142 के उप-नियम (1 ए) में निर्दिष्ट व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के लिए नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि नियम 142(1)(ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी होने और उसी का जवाब प्राप्त होने के बाद, सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान है, लेकिन 2017 के नियम 142(1 ए) और नियम 142(2 ए) के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

8. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हल्दिया बनाम कृष्णा वैक्स प्राइवेट लिमिटेड: **(2020)12 एससीसी 572** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा रखा है, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ यहां आसान संदर्भ के लिए उद्धृत किए गए हैं:

“13. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 11-ए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते समय, विभाग द्वारा केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है, जिसके आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। निर्धारण तभी होता है जब जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस संबोधित किया जाता है, उसके द्वारा प्रतिक्रिया या प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जाता है। अपने उत्तर के एक भाग के रूप में, संबंधित व्यक्ति सभी संभावित मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद ही निर्धारण या निर्णय पर पहुंचा जाता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने और निर्धारण पर पहुंचने से पहले ही, मामले को उक्त आंतरिक आदेश के विरुद्ध अपील में ले जाया गया। इसलिए, अपीलकर्ता का यह कहना उचित था कि अपील स्वयं अपरिपक्व थी।

14. इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आबकारी कानून अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और सामान्यतः किसी रिट न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा तथा संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले उस प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां उठानी होंगी जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया हो तो कानून के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार निवारण का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत संघ बनाम गुवाहाटी कार्बन लिमिटेड मामले में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि, “उत्पाद शुल्क कानून उत्पाद शुल्क मामलों में निवारण प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण संहिता है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट द्वारा याचिका पर विचार करना उचित नहीं हो सकता है”, जबकि मल्लाडी ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में यह टिप्पणी की गई थी:

“...उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में यह माना है कि अपीलकर्ता को सबसे पहले उस प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां

उठानी चाहिए, जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यदि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो उसे उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई है...हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने केवल कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट याचिका को खारिज करके बिल्कुल सही किया था।”

15. इस प्रकार यह सर्वविदित है कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने पर रिट याचिका पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, जब उच्च न्यायालय ने याचिका पर आरंभ में विचार किया था, तब कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था और विभाग को प्रथम दृष्टया यह विचार करने का निर्देश दिया था कि क्या मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध है।

9. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णय अलग-अलग तथ्यों पर आधारित हैं, क्योंकि उन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को अभी तक कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

11. 2017 के नियमों के नियम 142(1 ए) और 142(2 ए) को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि सक्षम अधिकारी के लिए यह विवेकाधीन है कि वह या तो सूचना जारी करे या न करे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, एक सूचना जारी की गई है और जिस व्यक्ति को सूचना भेजी गई है, उसने प्रस्तावित देयता के विरुद्ध प्रस्तुतियाँ दाखिल की हैं। फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 ए या फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 ए के भाग-बी में, 2017 के नियमों के नियम 142 के उप-नियम (1 ए) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के संबंध में न्यायनिर्णयन के लिए नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

12. हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों से इस कारण से भिन्न राय रखते हैं कि नियमों में सुनवाई का अवसर देने और प्रस्तावित देयता के खिलाफ किए गए प्रस्तुतियों पर निर्णय लेने का प्रावधान नहीं है। 2017 के नियमों का नियम 142(1 ए), मूल रूप से, केवल एक संचार है, जिसे 'उचित अधिकारी', यदि वह ऐसा महसूस करता है, दे सकता है। करदाता का अधिकार 2017 के नियमों के नियम 142(1 )( ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद ही उत्पन्न होता है, जिस स्थिति में नियमों के तहत सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान है। विभिन्न चरणों में सुनवाई का अवसर देने पर विधायिका द्वारा विचार नहीं किया गया था और इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों से भिन्न राय

रखते हैं। आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम और वित्तीय निहितार्थ वाले नियमों की व्याख्या उसी तरीके से की जानी चाहिए जैसा कि प्रख्यापित किया गया है। आयकर आयुक्त :**2010** आईएनएससी **535** ने टिप्पणी की कि यह एक सामान्य कानून है कि किसी कर-संबंधी कानून की व्याख्या कठोरता से की जानी चाहिए। किसी कर-संबंधी अधिनियम में, केवल संबंधित प्रावधान में कही गई बातों पर ही ध्यान देना होता है। कर के संबंध में कोई पूर्वधारणा नहीं है। कुछ भी न तो पढ़ा जाए, न ही कुछ निहित किया जाए। किसी भी प्रकार के आशय की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी कर-संबंधी कानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय को कानून के शब्दों को ध्यान से देखना चाहिए और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। किसी कर-संबंधी कानून की व्याख्या करते समय कठिनाई, अन्याय और समता के विचार पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं।

13. चूंकि वर्तमान मामले में केवल सूचना दी गई है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल कार्यवाही को रोकने के लिए दायर की गई है, जो प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है।

14. परिणामस्वरूप, हमें रिट याचिका में कोई बल नहीं मिला, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

15. स्थगन आवेदन और/या कोई अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा हो जाता है।

(प्रवीर भटनागर), जे

(पंकज भंडारी), जे

प्रीति असोपा /8

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी